

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. **Case No 9342/2022 Shri Anand Tamrakar, Prop., 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Mine in an area of 7.0 ha. (50,000 cum per annum) (Khasra No. 39) Village - Mawaighat-2, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 39), Village - Mawaighat-2, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1697 दिनांक 03/08/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, तथा कुल रकबा 24.00 हे. होता है तथा इस खदान का स्वयं का क्षेत्रफल भी 07.00 हे. अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका (पेज न. 74) के सरल क्रमांक-08 पर माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल (60 प्रतिशत) - 1,26,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 50,000 घन मीटर

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है । यह रेत खदान केन नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान के पूर्वी भाग से नदी का कुछ बहाव दिखाई दे रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र के जिस भाग से नदी बह रही है, वहाँ पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:-

1. रेत खनन का प्रकरण होने के कारण यदि आवंटित खनन क्षेत्र में एक्वेटिक फाउना का ब्रीडिंग क्षेत्र या अन्य कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड़, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड माईनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
6. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. आवंटित खनन क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एग्रोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. चूंकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये ।

11. ग्रामसभा एन.ओ.सी. ऑनलाईन उपलब्ध नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A.II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
13. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है ।
14. वन अधिकारियों से चर्चा कर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की संभावनाओं को भी तलाशा जाये, क्योंकि इस जिले की सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की हैं तथा कुल क्षेत्रफल 10.00 हे. से ज्यादा है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका एक संक्षिप्त विवरण जिसमें कुल लागत, प्रजातियों का विवरण (रख-रखाव के साथ) तथा वन क्षेत्र का नाम के साथ प्रस्तुत करें ।

2. **Case No 9343/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 7.0 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 01), Village - Kararaganj, Tehsil - Nowgaon, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01), Village - Kararaganj, Tehsil - Nowgaon, Dist. Chhatarpur (MP) 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री आनंद ताम्रकार, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1696 दिनांक 03/08/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, तथा कुल रकबा 14.00 हे. होता है तथा इस खदान का स्वयं का क्षेत्रफल भी 07.00 हे. अतः यह प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है, जिसकी तालिका (पेज न. 77) के सरल क्रमांक-37 पर माईनेवल मिनरल पोटेन्शियल (60 प्रतिशत)-1,26,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 25,000 घन मीटर की हेतु टॉर के लिए आवेदन किया गया है । यह रेत खदान धसान नदी पर स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन रेत खदान का सम्पूर्ण भाग नदी में डूबा दिखाई दे रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्रस्तावक ने बताया कि यह गूगल इमेज वर्षाकाल के समय (अक्टूबर-22) की है जिस कारण आवंटित खनन् क्षेत्र में पानी भरा दिख रहा है किंतु दिसम्बर-जनवरी से पानी उतरने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जो जनवरी-21 की गूगल इमेज से स्पष्ट होता है । प्रस्तुतीकरण पश्चात् समिति ने अनुशंसा की कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ मय संबंधित खनिज अधिकारी का प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन् क्षेत्र में खनन् हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर की अनुशंसा करती है:-

1. रेत खनन् का प्रकरण होने के कारण यदि आवंटित खनन् क्षेत्र में एक्वेटिक फाउना का ब्रीडिंग क्षेत्र या अन्य कोई संवेदनशील क्षेत्र हो तो उसकी जानकारी ई.आई.ए. रिपोर्ट में मय संरक्षण योजना के प्रस्तुत करें ।
2. खनिज परिवहन के दौरान परिवहन मार्ग पर रिफ्लेक्टरों की स्थापना, स्पीड ब्रेकर एवं रोड जंक्शन के विकास के लिए उपयुक्त बजट पर्यावरण प्रबंधन योजना में शामिल कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवंटित लीज के पूर्वी भाग से एक छोटी धारा का प्रवाह है, अतः परिवहन मार्ग प्रस्तावित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि उसका प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा इसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाये ।
4. यदि लीज एरिया के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में कोई रोड, ब्रिज/या अन्य कोई सिविल निर्माण जैसे : स्टापडेम अथवा कॉजवे इत्यादि लीज में या लीज के आसपास स्थित हो तो वहाँ मॉनिटरिंग एवं इंफोर्समेंट गाइडलाइन, 2020 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित) के अंतर्गत सुरक्षित दूरी छोड़े एवं इसका सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. यदि नदी का प्रवाह आवंटित लीज क्षेत्र से हो रहा हो तो नदी के पानी के क्षेत्र को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़कर एवं यदि कोई सहायक नदी / नाला आवंटित लीज क्षेत्र में मिल रहा हो तो सेंड मारनिंग गाइडलाइन, 2016 एवं 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार उसे गैर खनन् के रूप में छोड़ते हुए संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वचन-पत्र कि यदि खनन् क्षेत्र के किनारों पर हरित क्षेत्र अस्तित्व में हो तो ऐसे क्षेत्रों को गैर खनन् क्षेत्र के रूप में सुरक्षित रखा जावेगा तथा संशोधित नक्शा (सरफेस मेप) योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
7. रेत परिवहन मार्ग को गूगन नक्शों में अंकित कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. आवंटित खनन् क्षेत्र के किनारों पर भू-क्षरण रोकने हेतु समुचित वृक्षारोपण योजना एवं आसपास स्थित शासकीय भूमि पर ड्रोन के माध्यम से सीड वॉल तकनीक पर आधारित वृक्षारोपण योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास शासकीय भूमि पर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाओं के निर्माण की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास की भूमि पर एगोफॉरेस्ट्री की संभावनाओं का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

11. चूँकि खदान नदी के क्षेत्र में स्थित है, अतः सम्पूर्ण खदान क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे कर उस पर संबंधित खनिज अधिकारी प्रमाणीकरण प्राप्त कर, खदान के सभी डी.जी.पी.एस. को-आर्डिनेट ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाये, जिससे गूगल इमेज में खदान का सम्पूर्ण क्षेत्र दर्शित हो सके। यदि डी.जी.पी.एस. सर्वे के पश्चात् प्राप्त को-आर्डिनेट तथा वर्तमान में अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित को-आर्डिनेट में कोई सुधार वांछित हो तो उसे संबंधित जिला खनिज अधिकारी के संज्ञान में लाकर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित कर उस पर अनुमोदन भी प्राप्त किया जाये।
12. ग्रामसभा एन.ओ.सी. ऑनलाईन उपलब्ध नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के O.M. No. Z-11013/57/2014-I.A.II (M) दिनांक 29/10/14 के अनुसार अध्ययन कर विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
14. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जियोटेग फोटोग्राफ प्रस्तुत करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवंटित खनन क्षेत्र में खनन हेतु स्वीकृत मात्रा में रेत उपलब्ध है।
15. वन अधिकारियों से चर्चा कर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की संभावनाओं को भी तलाशा जाये, क्योंकि इस जिले की सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की हैं तथा कुल क्षेत्रफल 10.00 हे. से ज्यादा है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका एक संक्षिप्त विवरण जिसमें कुल लागत, प्रजातियों का विवरण (रख-रखाव के साथ) तथा वन क्षेत्र का नाम के साथ प्रस्तुत करें।

3. Case No 9344/2022 M/s M.K.S. Engineering Company Pvt. Ltd, 01, Namak Kothi, North Civil Lines, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.50 ha. (Stone - 24997 Cum per annum, Murrum - 8384 Cum per annum) (Khasra No. 03 Part), Village - Ghutiya, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP).

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 03 Part), Village - Ghutiya, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP). 3.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री एश्वर्य सक्सेना (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियारिंग, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 749 दिनांक 10/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-दक्षिण भाग से होते हुए एक रोड़ निकल रहा है जो उत्तरी दिशा में हाईवे से जुड़ रही है तथा

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

दक्षिण दिशा में गांव से मिल रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह गांव वालों के आवागमन का रास्ता है । गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कच्चा रोड या पक्का रोड है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड की वास्तविक स्थिति व संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। गूगल इमेज के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवंटित क्षेत्र में एक केशर पूर्व से ही स्थापित है अतः इसकी उपयोग की स्थिति ई.आई.ए. में स्पष्ट की जाये । जबलपुर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत को छोड़कर अन्य गौण खनिज) अभी परीक्षण हेतु सेक को अप्राप्त है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 3363 दिनांक 07/12/21 अनुसार उक्त खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी अतः समिति की अनुसंशा है कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-दक्षिण भाग से होते हुए एक रोड निकल रहा है जो उत्तरी दिशा में हाईवे से जुड़ रही है तथा दक्षिण दिशा में गांव से मिल रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह गांव वालों के आवागमन का रास्ता है । गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कच्चा रोड या पक्का रोड है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड की वास्तविक स्थिति व संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित क्षेत्र में पूर्व से एक केशर व शेड स्थापित है, अतः सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

4. Case No 9347/2022 M/s M.K.S. Engineering Company Pvt. Ltd, 01, Namak Kothi, North Civil Lines, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 3.30 ha. (Stone - 24997 Cum per annum, Murrum - 8384 Cum per annum) (Khasra No. 19/1 Part), Village - Ghutiya, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP)

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 19/1 Part), Village - Ghutiya, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP). 3.30 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 17/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री एश्वर्य सकसेना (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 750 दिनांक 10/03/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा से 45 मीटर की दूरी पर एक रोड़ निकल रहा है जो उत्तरी दिशा में हाईवे से जुड़ रही है तथा दक्षिण दिशा में गांव से मिल रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह गांव वालों के आवागमन का रास्ता है । गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कच्चा रोड़ या पक्का रोड़ है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड़ की वास्तविक स्थिति व संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 3365 दिनांक 07/12/21 अनुसार उक्त खनिपट्टा में सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण (उत्खनिपट्टा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी अतः समिति की अनुसंशा है कि परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा से 45 मीटर की दूरी पर एक रोड़ निकल रहा है जो उत्तरी दिशा में हाईवे से जुड़ रही है तथा दक्षिण दिशा में गांव से मिल रही है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह गांव वालों के आवागमन का रास्ता है । गूगल इमेज के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह कच्चा रोड़ या पक्का रोड़ है अतः परियोजना प्रस्तावक इस रोड़ की वास्तविक स्थिति व संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. आवंटित क्षेत्र में पूर्व से एक केशर व शेड स्थापित है, अतः सम्पूर्ण विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉपट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

5. Case No 9345/2022 Shri Ramesh Kumar Mahule S/o Late Shri Ramdulare Mahule, Ward No. 15, Dist. Balaghat, MP – 481776 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10001 Cum per annum) (Khasra No. 21 Part), Village - Paraswara Chak, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 21 Part), Village - Paraswara Chak, Tehsil - Nainpur, Dist. Mandla (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रमेश कुमार महुले (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1332 दिनांक 22/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 06.61 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 230 मीटर की दूरी पर तथा पूर्वी दिशा में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड, उत्तर दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना एवं 50 मीटर पर नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मंडला जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके इस खदान के विवरण अंकित नहीं है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 230 मीटर की दूरी पर तथा पूर्वी दिशा में 360 मीटर की दूरी पर पक्का रोड, उत्तर दिशा में 90 मीटर पर जल रोकने की संरचना एवं 50 मीटर पर नाला है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
4. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
6. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।

6. Case No 9346/2022 Smt. Mamta W/o Shri Manoj, Owner, Amrit Colony, Gandhi Nagar, Dist. Mahoba, UP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (150000 Cum per annum) (Khasra No. 133(P)), Village - Saila, Tehsil - Maharajpur, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 133 Part), Village - Saila, Tehsil - Maharajpur, Dist. Chhatarpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ममता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स जियो ग्रीन इन्वायरो हाऊस, लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1065 दिनांक 28/04/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 05.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी, दक्षिण दिशा में 600 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड तथा पश्चिम दिशा में खदान अंदर से एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 18 के सरल क्रमांक-8 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी, दक्षिण दिशा में 600 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड तथा पश्चिम दिशा में खदान अंदर से एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना पीक पार्टिकल वैलोसिटी के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. सरफेस रनआफ मैनेजमेंट प्लान तथा परिवहन मार्ग (खदान के पहाड़ पर स्थित होने के कारण) ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इम्पेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

7. Case No 9348/2022 Shri Sanjeev Kumar S/o Shri Satyadev Dixit, M.S 51, Sector-D, Aliganj, Dist. Lucknow, UP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (150000 Cum per annum) (Khasra No. 133(P)), Village - Saila, Tehsil - Maharajpur, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 133 Part), Village - Saila, Tehsil - Maharajpur, Dist. Chhatarpur (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव कुमार (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री विजय कुमार मिश्रा, मेसर्स जियो ग्रीन इन्वायरो हाऊस, लखनऊ उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 26/05/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 05.00 हे. से अधिक होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 150 मीटर की दूरी पर आबादी, दक्षिण दिशा में 650 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड तथा पश्चिम दिशा में खदान अंदर से एक कच्चा रोड निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित जबलपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 18 के सरल क्रमांक-9 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 225 मीटर की दूरी पर आबादी, दक्षिण दिशा में 650 मीटर पर नदी, पूर्व दिशा में 65 मीटर पर कच्चा रोड तथा पश्चिम दिशा में खदान अंदर से एक कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः इनकी संरक्षण योजना पीक पार्टिकल वैलोसिटी के साथ ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. सरफेस रनआफ मेनेजमेंट प्लान तथा परिवहन मार्ग (खदान के पहाड़ पर स्थित होने के कारण) ई. आई.ए. के साथ प्रस्तुत करे।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपैक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आंवटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

8. **Case No 9352/2022 M/s Basa Buildcon Partner- Shri Abul Vakar S/o Shri Abdul Kalam, R/o- G-9, Jhumera Complex Near Hotel Manal, A.B. Road Vishwas Banjari, Post - Bhatkhedi, Tehsil - Mhow, District Indore (M.P.), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (75000 Cum per annum) (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1022/2), Village - Kheda, Tehsil - Pithampur, Dist. Dhar (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण आज सेक की 601वीं बैठक दिनांक 19/10/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

9. **Case No 9359/2022 M/s Jagati Mining Company Pvt. Ltd, House No.07, Peptech Town, Nowgaon Road, District- Chhatarpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & M-sand Quarry in an area of 16.0 ha. (1500000 Cum per annum) (Khasra No. 2005), Village - Goyara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)**

This is case of Stone & M-sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 2005), Village - Goyara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 16.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 19/10/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री समृद्ध अग्रवाल (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता, (ऑनलाईन) मेसर्स ग्लोबस इंडास्ट्रियल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1642 दिनांक 21/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है। चूंकि प्रश्नाधीन खदान का रकबा 16.00 हे. है अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के तीन दिशाओं पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में आबादी है तथा दक्षिण दिशा में एक कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र के अंदर से निकल रहा है अतः इस प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश क्रमांक

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

304/10 दिनांक 21/7/20 को ध्यान में रखते हुए संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) ने पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 13/9/22 के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि इस खदान का विवरण अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक 128 पर अंकित है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदित डी.एस.आर. ऑन लाईन अपलोड नहीं की है अतः परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन की अधिकतम उत्पादन क्षमता 11,05,263 घनमीटर/वर्ष तथा एम-सेंड की अधिकतम उत्पादन क्षमता 03,94,737 घनमीटर/वर्ष हैं, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में विवरण इसी के अनुसार प्रस्तुत किये जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व विशिष्ट शर्तों के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :-

1. प्रश्नाधीन खदान के तीन दिशाओं पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर में आबादी है तथा दक्षिण दिशा में एक कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र के अंदर से निकल रहा है अतः इस प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. के आदेश क्रमांक 304/10 दिनांक 21/7/20 को ध्यान में रखते हुए संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे हैं, अतः उसकी प्रजाति, ऊँचाई एवं गirth फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
3. सरफेस रनआफ मेनेजमेंट प्लान तथा परिवहन मार्ग (खदान के पहाड़ पर स्थित होने के कारण) ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
5. अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन की अधिकतम उत्पादन क्षमता 11,05,263 घनमीटर/वर्ष तथा एम-सेंड की अधिकतम उत्पादन क्षमता 03,94,737 घनमीटर/वर्ष हैं, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में विवरण इसी के अनुसार प्रस्तुत किये जाये।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाइल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
7. आवंटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाइल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
8. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजिकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 19 अक्टूबर 2022

10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लान, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैंड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. के साथ अनुमोदित डी.एस.आर. जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो प्रस्तुत करे ।
13. वन अधिकारियों से चर्चा कर वन क्षेत्र में वृक्षारोपण की संभावनाओं को भी तलाशा जाये, क्योंकि खदान का कुल क्षेत्रफल 16.00 हे. है, अतः ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका एक संक्षिप्त विवरण जिसमें कुल लागत, प्रजातियों का विवरण (रख-रखाव के साथ) तथा वन क्षेत्र का नाम के साथ प्रस्तुत करें ।

10. Case No 8634/2021 M/s Rockphailer Gramudhyog Sewa Sansthan, Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 21.10 ha. (6,00000 cum per annum) (Khasra No. 201/1), Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Noida (U.P.)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 201/1), Village - Mudahara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 21.10 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 526वीं दिनांक 11/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई. आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

आज दिनांक 08/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री मनोज कुमार मिश्रा (अधिकृत प्रतिनिधि) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के पांडे तथा श्री अमर यादव, मेसर्स ए सीरीज इंवायरोटेक इंडिया प्रा0. लि0., नोएडा (उ.प्र.), उपस्थित हुए उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान क्षेत्र दक्षिण-पश्चिमी दिशा में 02 जलीय संरचना है, क्रमशः 60 मीटर व 245 मीटर पर स्थित है तथा एक प्राकृतिक नाला दक्षिण दिशा में 110 मीटर पर स्थित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन व सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए हैं तथा सेटलड वाटर ही निस्सारित किया जावेगा । इसी प्रकार 01 कच्चा रोड़ आवंटित क्षेत्र से निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पगडंडी है तथा वर्तमान में उनके खदान का पहुंच मार्ग भी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान शासकीय भूमि पर है जिसमें कुल 32 पेड़ लगे हैं, जिसकी इन्वेंट्री ई.आई.ए. में सलग्न है । खनन क्षेत्र में विद्यमान कुल 32 पेड़ में से 09 पेड़ बैरियर जोन में होने के कारण नहीं काटे नहीं जायेंगे तथा 23 पेड़ (बबूल, खैर एवं पलाश) काटे जायेंगे एवं उसके एवज 230 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे ।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत खसरा न0. 201/1 के पी.-2 फार्म में लगभग 1500 पेड़ों का विवरण (कैफियत कॉलम) दर्ज है जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा इसी खसरे में आवंटित क्षेत्र 21.10 हे. में मात्र 23 वृक्षों की इन्वेन्ट्री ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की है, जिससे विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो रही है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खसरे का कुल क्षेत्रफल लगभग 45 हे0. है जो सम्पूर्ण क्षेत्र में स्थित पेड़ों की संख्या दर्शा रहा है, जबकि उनके लीज क्षेत्र (21.10 हे0.) में 23 पेड़ लगे हुये हैं। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे उपरोक्त संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें साथ ही लीज एरिया में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री (प्रजातिवार उंचाई, गोलाई) के सत्यापन हेतु ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें।

इसी प्रकार समिति ने पाया कि खनिज निरीक्षक के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28/12/2020 में 500 मी. के परिधि के अंतर्गत दी गई जानकारी के बिन्दु क0. 1(जे) के अनुसार आवेदित स्थल पर “धार्मिक स्थल” स्थित है। अतः परियोजना प्रस्तावक सरफेस मेंप पर इसे अंकित करते हुए यह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि यह मंदिर पुरातत्व महत्व का तो नहीं है, यदि होतो तत्संबंध में पुरातत्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें एवं यदि पुरातत्व महत्व का नहीं है तो वहाँ पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नलिखित जानकारीयां समिति द्वारा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:-

1. खसरा न0. 201/1 के पी.-2 फार्म में कैफियत कॉलम लगभग 1500 पेड़ों का विवरण दर्ज है। जबकि परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र (21.10 हे0.) में 23 पेड़ लगे हुये हैं। अतः इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करें साथ ही लीज एरिया में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री (प्रजातिवार उंचाई, गोलाई) के सत्यापन हेतु ड्रोन विडियोग्राफी प्रस्तुत करें।
2. खनिज निरीक्षक के द्वारा जारी पत्र दिनांक 28/12/2020 में 500 मी. के परिधि के अंतर्गत दी गई जानकारी के बिन्दु क0. 1(जे) के अनुसार आवेदित स्थल पर “धार्मिक स्थल” स्थित है। अतः परियोजना प्रस्तावक सरफेस मेंप पर इसे अंकित करते हुए यह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर यह जानकारी प्रस्तुत करें कि यह मंदिर पुरातत्व महत्व का तो नहीं है, यदि होतो तत्संबंध में पुरातत्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें एवं यदि पुरातत्व महत्व का नहीं है तो वहाँ पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर उसकी संरक्षण योजना प्रस्तुत करें।
3. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
4. समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. जिसमें मिस्ट फॉगर, गेम प्रुफ फेंसिंग का प्रस्ताव शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।
5. प्रस्तुतीकरण में सी.ई.आर. लागत रु. 02.40 लाख दर्शाई गई हैं जिसे परियोजना लागत के साथ स्पष्ट करें।
6. जन-सुनवाई प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों द्वारा संबंधित सुझाये गये पानी की टंकी का निर्माण, नाली का निर्माण, तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण संबंधी कार्य को समिति द्वारा सुझाये अनुसार परियोजना लागत से तुलना करते पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना प्रस्तुत करें।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल ऑनलाईन ए.डी.एस. के माध्यम से अपलोड की गई है, जिसे राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के समक्ष रखा गया। आज दिनांक 19/10/22 को परियोजना प्रस्तावक प्रस्तावक श्री मनोज कुमार मिश्रा (अधिकृत प्रतिनिधि-ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आर.के पांडे तथा श्री अमर यादव (ऑनलाईन) मेसर्स ए सीरीज इंवायरोटेक इंडिया प्रा0. लि0., नोएडा (उ.प्र.), उपस्थित हुए उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 2182 दिनांक 18/10/22 के माध्यम से यह सूचित किया है कि खसरा नं. 201/1 के पी.-2 फार्म में 1356 वृक्षों का विवरण दर्ज हैं, 201/1 को कुल रकबा 43.932 हे. है जिसमें से प्रतिबंधित क्षेत्र 22.832 हे. है प्रतिबंधित क्षेत्र को मानचित्रकार द्वारा काटकर बचा हुआ शेष रकबा 21.01 उपलब्ध क्षेत्र स्वीकृत किया गया है। खनिज निरीक्षक के स्थल निरीक्षण पश्चात् पाया गया कि स्वीकृत क्षेत्र में कुल 31 पेड़ लगे हुए हैं एवं अन्य लगभग 1300-1325 वृक्ष दक्षिण-पश्चिम दिशा में प्रतिबंधित क्षेत्र 22.832 हे. के अंदर स्थित हैं एवं धार्मिक स्थल से नियमानुसार पर्याप्त प्रतिबंधित दूरी छोड़कर लीज स्वीकृत है। समिति की अनुशंसा है कि आवंटित खनन क्षेत्र 10.00 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण वृक्षारोपण वन विभाग के माध्यम से कराया जाये तथा राशि वन विभाग के एफ.डी.ए. खाते में जमा कराई जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारीयों संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता स्टोन – 6,00,000 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 29.52 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 25.92 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 04.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सामाजिक कल्याण के लिए सी.ई.आर	
लोक सुनावई के आधार पर सी.ई.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में दो बार नियमित स्वास्थ्य की व्यवस्था, (COVID1-19 परीक्षण, रक्तचाप, मधुमेह, मौखिक स्वच्छता) व्यवस्था की जायेगी।	50,000 / -
ग्राम मुदहारा के प्राथमिक विद्यालयों में 01 सोलर पैनल की स्थापना कराई जायेगी।	30,000 / -
मुदहारा ग्राम में पशुओं का टीकाकरण कराया जायेगा।	20,000 / -
ग्राम मुदहारा के आंगनबाडी केन्द्र में खाना पकाने के लिए और भोजन परोसने के लिए और बच्चों को खाने के लिए बर्तन और 1 साल तक पोषणआहार का वितरण किया जायेगा।	80,000 / -
ग्राम मुदहारा में खान श्रमिकों एवं ग्रामीणों में पर्यावरण एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम कराया जायेगा।	10,000 / -
10 नग उज्ज्वला योजना के तहत सोलर कुकर/एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जायेगा।	50,000 / -

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

लीज एरिया के समीप तालाब का गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु तालाब के किनारे वृक्षारोपण साथ ही बैठक व्यवस्था की जायेगी।	2,00,000 /—
वृक्षारोपण (फल और चारा देने वाले पौधों का वितरण) से संबंधित कार्य ईएमपी में शामिल है।	
योग	4,40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 25,500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बेरियर जोन	सिस्सू, खमेर, नीम, पीपल, शीशम, चिरौल, कंरज, चिरौल सीताफल, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	10,200
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, कंरज, महुआ, इत्यादि।	900
3	पश्चिम दिशा की ओर तालाब के किनारों में वृक्षारोपण	कदम्ब, अमलतास, पीपल, बरगद, नीम, कचनार, गुलमोहर इत्यादि।	1000
4.	मुदहारा ग्रामवासियों में वितरण हेतु	मुनगा, अमरुद, बेल, इमली, आंवला, कटहल, महुआ, आम, इत्यादि।	13,340
5	प्राथमिक विद्यालय प्रकाश बम्हौरी।	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार, गुलमोहर इत्यादि।	60
कुल			25,500

11. जिला सर्वेक्षण रिपोर्टों पर चर्चा – जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आज की बैठक के दौरान प्रस्तुत की गयी। यह प्रकरण एजेण्डा में सूचीबद्ध नहीं था किंतु संबंधित खनिज अधिकारियों/निरीक्षकों के अनुरोध पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान की गई।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

कार्यालय कलेक्टर के पत्र क्र0. 11099 दिनांक 12/10/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट— श्योपुर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप समिति का अनुमोदन एवं जिला पोर्टल पर रखने के उपरांत प्रस्तुत की गई है। जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई, जिसमें पाया:—

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के चैप्टर –09 (पेज न0. 15–22) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे गई है।
- जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एवं प्रजातियों की जानकारी में नहीं दी गई है
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज न0. 31–32 में जो मेटर दिया गया है वह स्पष्ट पढ़ने में नहीं आ रहा है। इन पेजों में Text आपस में मिल रहा है ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि श्योपुर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गौण खनिज एवं रेत खनिज को समिति की सुझाई गयी उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत की जावे।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
 38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - l. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 19 अक्टूबर 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

601वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टूबर 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained